37 Written Answers

लघु उद्योग सेवा संस्था में एक चार मास का पूर्गुकालिक पाठ्यक्रम प्रायोजित किया गया था जो 1 नवम्बर, 1968 को प्रारम्भ हुमा भौर 28 फरवरी, 1969 को समाप्त हुमा। इस में कुल 58 इंजीनियरों को प्रशिक्षगु दिया गया। शिक्षा मन्त्रालय ने उस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक स्नातक इंजीनियर को 250 स्पये प्रतिमास तथा 150 स्पये प्रतिमास डिप्लोमा घारी इंजी-नियर को गृत्ति दी।

- (3) िझिक्षा मन्त्रालय ने 1949-50 में एक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदि की योजना झारम्भ की जिस का उद्देश्य तकनीकी संस्थामों से शिक्षा प्राप्त स्नातकों तक्षा डिप्लोमा धारी इंजीनियरों की ग्रावश्यक व्यावहा-रिक प्रशिक्षरंग प्रदान करना था ताकि वे लाभकारी म्राजीविका प्राप्त कर सकें । इंजीनियरी तथा तकनालोजी के स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को क्रमश; 250 रुपये प्रति मास 150 रुपये प्रतिमास ग्राजीविका वर्त्ति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षगा सामान्यतः 1 वर्षं का होता है ।
- (4) इंजीनियरों, कीरीगरों तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापना के लिए विसीय सहायता नामक एक योजना तैयार की गई है भ्रौर उसे राज्य सरकारों को "भ्रादर्श योजना" के रूप में भेजा गया है ताकि वे इसे म्रपने राज्य क्षेत्र में सहायतार्थ स्वीकार करें।
- हाई प्रेझर (उच्च दाव वाले) उपकरमों तथा हैवी र्यूटी कम्प्रेसरों का निर्माख
 - *854. भी महाराज सिंह भारती : भी महापाल सिंह :

भी वे**एी इांकर झर्माः** भी दी० चं० झर्माः

क्या ग्रोडोगिक विकास, ग्राम्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की क्रेपा करेंगे कि :

(क) क्या चौधी पंचवर्षीय योजना में हाई प्रैशर (उच्व दाब वाले) उपकरण तथा हैवी इ्यूटी कम्प्रैशर बनाने के बारे में कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) क्या उससे देश की सारी मावइयकता पूरी हो जायेगी ; मौर

(ग) यदि हाँ, तो तरसम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

ग्रीत्रोगिक विकास, ग्रांतरिक व्यापार तथा समयोग-कार्य मन्त्री (भी फलरहीन प्रसी प्रहमद): (क) से (ग). सरकार ने भारी कम्प्रैसरों झौर विशेष पम्पों का निर्माण करने के लिए जिनकी मावश्यकता उर्वरक उद्योग. रसायन झौर पेटोरसायन संयंत्रों तथा इस्पात संयंत्रों को पड़ती है, सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का निष्चय किया है। पम्प ग्रीर कम्प्रैशर बनाने के लिए देश में उपलब्ध विद्यमान उत्पादन सुविधाम्रों मौर क्षमता को भ्यान में रखते हए तथा चौथी पंच-वर्षीय योजना की भवधि में इनकी संभावित मावइयकता को घ्यान में रखते हुए इस परि-योजना की क्षमता 6,000 मी॰ टन प्रतिवर्ष निइचित करने का निर्एंग किया है इस परि-योजना में उसी किस्म के पम्पों मौर कम्प्रैशरों का निर्माण करने का विचार है जिनका इस समय देश में निर्माण नहीं हो रहा है तथा वे सभी वस्तुएं, जिनके विकास भौर उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में रुचि दिखाई है, इसके निर्माण कार्यक्रम से निकाल दी गई हैं ; इस परियोजना में लगभग 10.68 करोड रुपये लागत माने का मनुमान है। जिसमें मोटे तौर से 1 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा का व्यय भी सम्मिलित है। मंतिम उत्पादन लगभग 10.8 करोड़ रुपये प्रतिवर्षं का होगा। इसके

म्रतिरिक्त, 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था बस्ती निर्माएग के लिए की गई है। इस प्रकार कुल मनुमानित लागत 11.68 करोड़ रुपये हो शायेगी।

Export of Car Components by M/s-Hindustan Motors

*555. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP-MENT, INTERNAL TRADE AND COM-PANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Hindustan Motors are exploring the possibilities of exporting car components;

(b) if so, whether the exports would not hit the automobile production in the country;

(c) the estimated foreign exchange earned through the exports ; and

(d) the quantity of foreign exchange spent on importing auto spares etc.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). M/s. Hindustan Motors have only indicated so far that they are exploring with their collaborators, the possibilites of exporting automobile components, including car components. No specific proposals have been received so far from them. There is no reason to apprehend that such exports would hit automobile production in the country. For one thing, there is at present considerable spare capacity in Hindustan Motors on account of very low volume of production of commercial vehicles, and for another, the precise volume of exports is yet to be known. For the same reason, no estimate is possible at this stage of the earnings of foreign exchange through such exports.

(d) The amount of foreign exchange sanctioned to the automobile manufacturers during the year 1968-69 for import of motor vehicle parts is Rs. 2.5 crores.

Hindustan Steel Limited

*556. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) the amount of subsidy given to the

Hindustan Steel Ltd. during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69;

(b) the foreign exchange allowed to the Hindustan Steel Ltd. during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69;

(c) the foreign exchange earned by the Hindustan Steel Ltd. during the last three years by exports of steel etc.;

(d) whether the Hindustan Steel Ltd. has achieved its targets of production ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA): (a) The amount of subsidy which accrued to HSL on exports amounted to Rs. 1 million in 1966-67, Rs. 38 million in 1967-68 and to Rs. 35 million during the period from April to December, 1968.

(b) H. S. L. were allowed foreign exchange for imports of spares and raw materials to the extent of Rs. 121'448 million in 1966-67 and Rs. 79.371 million in 1967-68. The information for 1968-69 is not readily available.

(c) The FOB value of exports by HSL during the last three years was Rs. 93 million in 1966-67, Rs. 309 million in 1967-68 and Rs. 331 million during the period from April, 1968 to January, 1969.

(d) and (e). H. S. L. had a programme of production of 1.58 million tonnes of pig iron for sale and 2.726 million tonnes of saleable steel for the year 1968-69. Against this target, actual production is likely to be of the order of 1.116 million tonnes of pig iron and 2.668 million tonnes of saleable steel. The gap is not very significant and is mainly due to much-needed capital repairs to Blast Furnaces, Open Hearth furnaces and some of the mills, labour troubles in Durgapur etc.

Recession in Machine Tool Industry

*557. SHRI CHENGALRAYA NA1DU : SHRI P. C. ADICHAN :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the utilization of production capacity in the machine tool industry is ranging between 10 per cent and 80 per cent and at an average of 46 per